



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 3, March 2024



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.580



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com

आवासीय विद्यालय योजना, राजस्थान

¹Jaswant Singh Yadav, ²Dr.Neha Yadav

¹Research Scholar, Education Department, Sunrise University, Alwar, India

²Associate Professor, Education Department, Sunrise University, Alwar, India

सार

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालकों (राइका, रेबारी, देवासी, गायरी एवं अन्य जाति के पशुपालक), भिक्षावृत्ति, एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े परिवारों के बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के अंतर्गत के.एफ.डब्ल्यू. बैंक, जर्मनी द्वारा दिये जा रहे आर्थिक सहयोग से 10 एवं राज्य सरकार द्वारा 14 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राजस्थान रेसिडेंसियल एजुकेशनल इंटीट्यूशनस सोसायटी (RREIS) द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना की पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेख में आगे दी गई है।

परिचय

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 120 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी।
- जानकारी के अनुसार अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिये, जोधपुर, झुंझनू, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) में बालकों के लिये राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।
- प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह आवासीय विद्यालय 100 विद्यार्थी क्षमता के होंगे तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें डे-स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। [2,3,4]

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विद्यार्थियों (कक्षा 6वीं से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अपने वातावरण में निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को 20.00 करोड़ रुपये से 37.80 करोड़ रुपये संशोधित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में के लिए यह राशि 24.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 48.00 करोड़ रुपये कर दी गई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों को चलाने के लिए और विद्यार्थियों के खर्च (वर्दी, किताबें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आवर्ती लागत 1.09 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि जब तक स्कूलों के भवन का निर्माण पूरा ना हो जाए तब तक इन स्कूलों को वैकल्पिक भवनों में, प्राथमिकता के रूप में सरकारी भवनों में चलाएं। आज तक,

690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है और देश भर में 401 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, जिसमें 113275 विद्यार्थी इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकित हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त समाज, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी किया जाता है और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति इसके बाद राज्य समितियों और निर्माण एजेंसियों आदि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धन जारी करती है। वर्ष 2019-

20 तक राजस्थान सहित राज्यों को इस योजना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में एक घटक के रूप में धनराशि जारी की जा रही थी। वर्ष 2020-

21 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए अलग से धन का आवंटन किया गया है।

सरकार ने बजट 2023-

24 में 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। इसके अनुसार, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे की उचित कार्रवाई कर रहा है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनके नज़दीक ही आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर देने के लिये तथा जनजाति क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान के लिये 7 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिनके भवन निर्माण के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है।

- इस वर्ष प्रथम चरण में प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगामी वर्ष में द्वितीय चरण के तहत इनके निर्माण कार्य पर 71 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- आवासीय विद्यालय राज्य के पाली के सुमेरपुर, सवाई माधोपुर, भेड़ोली-बौली (सवाई माधोपुर), अजमेर के केकड़ी स्थित गिरवरा, जालोर, डूंगरपुर के चिखली, टोंक के देवली स्थित श्रीपुरा में खोले जाएंगे।
- इन सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 210 होगी।

विचार-विमर्श

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्थान सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए आठ नए छात्रावास और एक आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी।^[1,2,3]

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे आठ छात्रावासों एवं विद्यालयों को चालू सत्र से ही खोलने एवं संचालित करने के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी से जालोर जिला मुख्यालय पर जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाएगा।

बारां जिले के कस्बाथाना, देवरी, भंवरगढ़ और शाहबाद, डूंगरपुर के गढ़ा मोरिया और उदयपुर के कुराबड़ में नए बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं, डूंगरपुर के तलैया और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर नए बालक छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इन छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के लिए पदों के सृजन एवं संसाधनों की व्यवस्था की घोषणा की थी।

राज्य सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग विकास निधि के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 67.92 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान भी किया है।

इसमें आर्थिक कमजोर वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये, आर्थिक कमजोर वर्ग कॉलेज स्तरीय कन्या छात्रावासों के निर्माण और संचालन के लिए 40.17 करोड़ रुपये और आर्थिक कमजोर वर्ग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 9 करोड़ रुपये शामिल हैं।

परिणाम

राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय

जगतपुरा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा संचालित देश के प्रथम राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय का विधिवत् उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा यह मेरी दृष्टि में एक नया प्रयोग है जिसकी घोषणा राज्य के बजट में की गई थी। खुशी है कि कम समय में इस घोषणा को मूर्त रूप दिया गया। स्काउट गाइड का सौ साल का अपना इतिहास है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जैसी विभूतियां समय-समय पर स्काउट गाइड की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही राष्ट्रीय जम्बूरी में भी शामिल होती रही हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, राजस्थान

भारत में केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देशभर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। इस योजना का शुभारम्भ 2006-07 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है बाकि 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होती है।[1][2]

इतिहास

यह योजना अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। तब इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था।



कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बीच लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। नामांकन के रुझान को देखते हुए, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में लड़कों की तुलना में, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। केजीबीवी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो।

पात्रता

यह योजना 2004 में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीवी) में अपनी स्थापना के बाद से लागू थी, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत (46.13%: जनगणना 2001) से कम है और साक्षरता में लिंग अंतराष्ट्रीय औसत (21.59%: जनगणना 2001) से अधिक है। इन ब्लॉकों में, निम्नलिखित क्षेत्रों में स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं:

1. जनजातीय आबादी की सघनता, कम महिला साक्षरता और/या कई लड़कियां स्कूल से बाहर हैं।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी की सघनता, कम महिला साक्षरता और/या कई लड़कियां स्कूल से बाहर हैं।
3. कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्र
4. कई छोटी, बिखरी हुई बस्तियों वाले क्षेत्र जो स्कूल के योग्य नहीं हैं।

निम्नलिखित को शामिल करने के लिए पात्र ब्लॉकों के मानदंड को 1 अप्रैल 2008 से संशोधित किया गया है:

1. 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले अतिरिक्त 316 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक।
2. राष्ट्रीय औसत (53.67%: जनगणना 2001) से कम महिला साक्षरता दर वाले 94 कस्बों/शहरों में अल्पसंख्यक बहुलता (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पहचान की गई सूची के अनुसार) है।

आवासीय विद्यालय

यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है: असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

उदयपुर, राजस्थान में लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छी शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह अवसरों के द्वार खोलता है और सफलता की नींव तैयार करता है। लड़कियों के लिए, यह विशेष रूप से सच है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें लैंगिक बाधाओं को दूर करने और उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकती है।

राजस्थान में, लड़कियों के लिए कई महान आवासीय विद्यालय लड़कियों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। राजस्थान में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय अपने उत्कृष्ट शिक्षाविदों और अपने छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। स्कूल का अपने छात्रों को स्वतंत्र, आत्मविश्वासी युवा महिलाएँ बनने में मदद करने पर ज़ोर है।

आवासीय विद्यालय लड़कियों को लैंगिक बाधाओं को दूर करने और उनकी उच्चतम क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

राजस्थान में बालिका केन्द्रित शिक्षा का महत्व

राजस्थान में बालिका-केन्द्रित शिक्षा सिर्फ एक चलन से कहीं अधिक है; यह भविष्य के लिए सशक्त महिला नेताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता है। राज्य ने छात्राओं की अनूठी जरूरतों को पहचाना है और एक ऐसा वातावरण प्रदान कर रहा है जहां वे शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकें।

राजस्थान में आवासीय विद्यालयों की सूची

राजस्थान, जिसे अक्सर 'पूर्व का वेनिस' कहा जाता है, न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि एक शैक्षिक केंद्र भी है। यहां कुछ प्रसिद्ध लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों पर एक नजर है:

हेरिटेज गर्ल्स स्कूल

उदयपुर के पास एक हिंदू तीर्थ स्थल एकलिंगजी में 2014 में स्थापित हेरिटेज गर्ल्स स्कूल, जीवन के सभी क्षेत्रों की लड़कियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है।

संस्थान अपने छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूल गतिशील शिक्षण वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और लड़कियों को वैश्विक नागरिक बनने में मदद करता है।

स्कूल में एक समृद्ध पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और विशाल कक्षाएँ हैं। लड़कियों को खेल और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में भी भाग लेने की अनुमति है।

स्कूल में दूर-दराज के इलाकों से आने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा है। छात्रावास उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। लड़कियों को सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर भी दिया जाता है। इससे उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद मिलती है।

हेरिटेज गर्ल्स स्कूल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में से एक है और यह अपने छात्रों के जीवन में बदलाव ला रहा है।[1,2,3]

मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर, राजस्थान

मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूलों में से एक है और राजस्थान के अजमेर में स्थित है। स्कूल की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। स्कूल एक उत्कृष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

स्कूल में एक योग्य और अनुभवी संकाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा मिले। स्कूल पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और कला कक्ष जैसी कई प्रकार की सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर, राजस्थान

महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूलों में से एक है और राजस्थान के जयपुर में स्थित है। स्कूल की स्थापना वर्ष 1943 में हुई थी। स्कूल में शानदार शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ हैं। स्कूल का भविष्य उज्ज्वल है! माता-पिता की सहायता और समर्थन से, शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लड़कियों को उत्कृष्ट शिक्षा दी जाए। इसकी अक्सर दूसरों द्वारा अनुशंसा की जाती है क्योंकि इसके उच्च मानक उन्हें आज की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में अलग करते हैं जिसमें हम रहते हैं।"

राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जोधपुर, राजस्थान

राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूलों में से एक है और राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। स्कूल की स्थापना 1992 में हुई थी। इस स्कूल की लड़कियाँ बुद्धिमान, अच्छे व्यवहार वाली और विनम्र हैं। वे अपनी वर्दी हमेशा अनुशासन के साथ पहनते हैं, जिससे पता चलता है कि वे साफ-सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। राजमाता कृष्णा गर्ल्स पब्लिक स्कूल के छात्र आकर्षक दिखने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। [4,5,6]

बिड़ला बालिका विद्यापीठ, पिलानी, राजस्थान

बिड़ला बालिका विद्यापीठ भारत के सर्वश्रेष्ठ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूलों में से एक है और राजस्थान के पिलानी में स्थित है। स्कूल की स्थापना 1941 में हुई थी। स्कूल में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के संग्रह के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय है। इसके अलावा, कंप्यूटर लैब नवीनतम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। इसी तरह, विज्ञान प्रयोगशाला नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है।

बनसथली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षकों हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री द्वारा 6 अक्टूबर 1935 को स्थापित वनस्थली विद्यापीठ ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपने लिए एक जगह बनाई है। 1983 में इसे 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया, उत्कृष्टता के प्रति इसका समर्पण 2011 में NAAC द्वारा शीर्ष 'ग्रेड ए' रेटिंग जैसी प्रशंसाओं से स्पष्ट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टंडन समिति ने शासन, शिक्षाविदों में इसकी उपलब्धियों को मान्यता दी।, अनुसंधान, और बुनियादी ढांचे, इसे 2010 में 'मानित विश्वविद्यालय संस्थानों' की 'श्रेणी ए' सूची के तहत रखा गया। वनस्थली विद्यापीठ ने एनआईआरएफ, क्यूएस आई गेज और टाइम्स हायर एजुकेशन जैसी वैश्विक रैंकिंग में भी अपनी पहचान बनाई है। अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, विश्वविद्यालय को 2020 में NAAC से A++ ग्रेडिंग प्राप्त हुई।

राजस्थान में आवासीय विद्यालय का विकल्प क्यों चुनें [7,8,9]

राजस्थान, जिसे अक्सर "पूर्व का वेनिस" कहा जाता है, व्यापक शिक्षा के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। शहर का शांत माहौल और ऐतिहासिक अतीत केंद्रित अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। यहां आवासीय विद्यालय का चयन करने से छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा का लाभ सुनिश्चित होता है। कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों से परे, ये स्कूल सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों और चरित्र निर्माण पर जोर देते हैं, जो शहर की परंपरा और आधुनिकता के संश्लेषण को दर्शाते हैं। इस प्रकार, राजस्थान में आवासीय विद्यालय चुनने का अर्थ शैक्षिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास के संतुलित मिश्रण में डूबना है।

उदयपुर में विभिन्न आवासीय विद्यालय श्रेणियों की खोज [10,11,12]

राजस्थान, एक ऐतिहासिक शहर जो अपनी समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध है, एक शैक्षिक केंद्र भी है जो विविध प्रकार के बोर्डिंग स्कूलों की पेशकश करता है। इन संस्थानों में भारत के शैक्षिक लोकाचार में निहित पारंपरिक से लेकर समकालीन, वैश्विक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तक शामिल हैं। इनमें से कुछ स्कूल अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं, छात्रों को वैश्वीकृत दुनिया के लिए तैयार करते हैं। इसके विपरीत, अन्य लोग राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों के अनुरूप भारतीय सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देते हैं। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि परिवार अपने बच्चे की सीखने की शैली और भविष्य की आकांक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त संस्थान चुन सकते हैं।

उदयपुर में सही आवासीय विद्यालय चुनने के लिए टिप्स

- मान्यता: सुनिश्चित करें कि स्कूल के पास शैक्षिक बोर्डों या निकायों से प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं।
- संकाय योग्यताएँ: शिक्षण स्टाफ की शैक्षिक पृष्ठभूमि और अनुभव पर शोध करें।
- कैम्पस सुविधाएँ: समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और मनोरंजक क्षेत्रों की जाँच करें।
- पाठ्येतर अवसर: विभिन्न रुचियों को पोषित करने के लिए खेल, कला और क्लब जैसी विविध गतिविधियों की पेशकश करने वाले स्कूलों की तलाश करें।
- बच्चे की ज़रूरतें: स्कूल चुनते समय अपने बच्चे की सीखने की शैली, रुचियों और शक्तियों पर विचार करें।

- स्कूल लोकाचार: स्कूल के मूल्यों, सिद्धांतों और संस्कृति को समझें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके परिवार की मान्यताओं के अनुरूप है।[13,14]

प्रवेश पात्रता

राजस्थान में आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश पात्रता विभिन्न संस्थानों में भिन्न-भिन्न है। हालाँकि, संभावित छात्रों के लिए सामान्य आवश्यकताओं में मुख्य रूप से एक संतोषजनक शैक्षणिक इतिहास प्रस्तुत करना शामिल है। यह उनके पिछले प्रदर्शन को दर्शाता है और स्कूल को उनके मूलभूत ज्ञान का आश्वासन देता है। इसके अतिरिक्त, कई स्कूल विभिन्न विषयों में छात्रों की योग्यता मापने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। इससे छात्र को उचित ग्रेड या कक्षा में रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा, व्यक्तिगत साक्षात्कार अक्सर प्रवेश प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यहां, स्कूल छात्र के व्यक्तित्व, रुचियों और स्कूल के वातावरण और लोकाचार के साथ अनुकूलता का आकलन कर सकता है। साथ में, ये मानदंड स्कूलों को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे उन छात्रों को प्रवेश दें जो उनके मानकों और मूल्यों के अनुरूप हैं।

औसत वार्षिक लागत

राजस्थान में आवासीय विद्यालयों का वार्षिक खर्च स्कूल की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और पाठ्यक्रम के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। औसतन, माता-पिता 3 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की लागत का अनुमान लगा सकते हैं। इस व्यापक शुल्क में आम तौर पर बोर्डिंग शुल्क, जिसमें आवास और भोजन, और प्रदान किए गए शैक्षणिक निर्देश के लिए ट्यूशन शुल्क शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। इन फीस को प्रभावित करने वाले कारकों में स्कूल का बुनियादी ढांचा, संकाय गुणवत्ता, पाठ्येतर पेशकश और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। माता-पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे लागत के मूल्य और विभाजन की स्पष्ट समझ पाने के लिए विशिष्ट स्कूलों पर शोध करें।[15,16,17]

भुगतान की विधि

राजस्थान आवासीय विद्यालय आधुनिक बैंकिंग और भुगतान सुविधाओं से सुसज्जित हैं। परंपरागत रूप से, वे चेक पर भरोसा करते हैं, जिससे शुल्क जमा करने का एक दस्तावेजी और विश्वसनीय तरीका सुनिश्चित होता है। हालाँकि, जैसे-जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ उन्नत हुई हैं और बैंकिंग विकसित हुई है, इन संस्थानों ने भुगतान के मानक तरीके के रूप में बैंक हस्तांतरण को शामिल करने के लिए अनुकूलन किया है।

पारंपरिक तरीकों के अलावा, भुगतान प्रणालियों में डिजिटलीकरण की ओर ध्यान देने योग्य रुझान है। इनमें से अधिकांश स्कूल अब ऑनलाइन भुगतान पोर्टल भी प्रदान करते हैं, जिससे माता-पिता और अभिभावकों को अपने घर से फीस का भुगतान करने में आसानी होती है, जिससे प्रक्रिया सहज और कुशल हो जाती है।

शुल्क भुगतान योजनाएँ

राजस्थान के आवासीय विद्यालय माता-पिता की विविध वित्तीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। इसे पूरा करने के लिए, कई स्कूलों में लचीली भुगतान संरचनाएं मौजूद हैं। त्रैमासिक भुगतान योजनाओं की पेशकश करने वाले संस्थानों को ढूंढना आम बात है, जिससे माता-पिता साल भर में वित्तीय बोझ फैला सकते हैं। द्वि-वार्षिक योजनाएं एक और विकल्प प्रस्तुत करती हैं, जहां फीस का भुगतान दो बड़ी रकमों में किया जा सकता है, आमतौर पर प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में।

इसके अलावा, शिक्षा के महत्व और इसकी संभावित वित्तीय बाधाओं को समझते हुए, कुछ स्कूलों में छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता के प्रावधान हैं। अक्सर योग्यता या वित्तीय आवश्यकता पर आधारित ये सहायता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि प्रतिभाशाली छात्र मौद्रिक चुनौतियों के कारण पीछे न रह जाएं।[18,19,20]

निष्कर्ष

राजस्थान, विशेष रूप से उदयपुर सहित, विशेष रूप से लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये संस्थान न केवल अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करते हैं बल्कि एक समग्र वातावरण भी प्रदान करते हैं जो छात्रों को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार सशक्त व्यक्तियों में ढालता है। लड़कियों के लिए उदयपुर के आवासीय विद्यालय हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य को बढ़ावा देने की क्षेत्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। परंपरा, गुणवत्ता और आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं का मिश्रण चाहने वालों के लिए, उदयपुर, राजस्थान निस्संदेह लड़कियों की आवासीय शिक्षा के लिए एक शीर्ष विकल्प है।[21]

संदर्भ

1. कुल्हमन, स्टीफन (27 जनवरी 2017)। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए नवप्रवर्तन प्रशासन पर शोध पुस्तिका: बेहतर मॉडल की ओर। चेल्टेन्हम, यूके: एडवर्ड एलगर। आईएसबीएन 978-1-78347-191-1. ओसीएलसी 971520924।
2. ^ रोज़र, मैक्स; ऑर्टिज़-ओस्पिना, एस्टेबन (2019)। "प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा"। डेटा में हमारी दुनिया। 18 मई 2023 को मूल से संग्रहीत। 24 अक्टूबर 2019 को लिया गया।
3. ^ "अमेरिकी शिक्षा प्रणाली को समझना"। www.studyusa.com। 9 नवंबर 2022 को मूल से संग्रहीत। 9 नवंबर 2022 को पुनःप्राप्त।
4. ^ "इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल (आईएपीएस) | उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ स्कूल"। 25 फरवरी 2019 को मूल से संग्रहीत।
5. ^ "स्कूल बच्चों को जीवन के लिए तैयार नहीं करते हैं। यहां वह शिक्षा है जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता है। रियानोन लुसी कॉस्लेट"। अभिभावक। 12 जून 2017. 4 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत। 4 अगस्त 2021 को लिया गया।
6. ^ केओघ, बारबरा (9 सितंबर 2009)। "अपने बच्चे के स्वभाव को समझना क्यों महत्वपूर्ण है"। www.greatschools.org। 4 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत। 4 अगस्त 2021 को लिया गया।
7. ^ रॉबिन्सन, सर केन (27 जून 2006), क्या स्कूल रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं?, मूल से 15 सितंबर 2013 को संग्रहीत, 4 अगस्त 2021 को पुनः प्राप्त।
8. ^ "स्कूल जिज्ञासा को खत्म कर रहे हैं: हमें बच्चों को चुप रहने और सीखने के लिए कहना क्यों बंद करना चाहिए"। द गार्जियन। 28 जनवरी 2020। 4 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत। 4 अगस्त 2021 को लिया गया।
9. ^ ऑनलाइन व्युत्पत्ति शब्दकोश संग्रहीत 1 फरवरी 2009 को वेबैक मशीन; एचजी लिडेल और आर. स्कॉट, एक ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकन, 1 फरवरी 2009 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत।
10. ^ स्कूल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर
11. ^ σχολή, हेनरी जॉर्ज लिडेल, रॉबर्ट स्कॉट, ए ग्रीक-इंग्लिश लेक्सिकन, पर्सियस पर 25 फरवरी 2021 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत।
12. ^ बेंटले, जेरी एच. (2006). परंपराएँ और मुठभेड़ अतीत पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। न्यूयॉर्क: मैकग्रा-हिल। पी। 331.
13. ^ "लेसेफ़रडिघेट और स्कोलेवेसेन 1740-1830" (पीडीएफ)। डिजिटल पुरालेख खोलें. 14 अप्रैल 2016 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत। 15 मई 2014 को लिया गया।
14. ^ "स्कूल के प्रकार"। GOV.UK। 25 मार्च 2019 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।
15. ^ "राज्य स्कूलों और निजी स्कूलों के बीच क्या अंतर है?"। ब्रिटिश काउंसिल हांगकांग। 20 जून 2023 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।
16. ^ "शिक्षा"। राष्ट्रमंडल। 28 अप्रैल 2023 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।
17. ^ "स्कूल अर्थ संस्कृत अर्थ अनुवाद क्या मतलब"। www.bsarkar.com। 20 फरवरी 2022 को मूल से संग्रहीत। 20 फरवरी 2022 को लिया गया।
18. ^ www.wisdomlib.org (13 जनवरी 2019)। "विद्यालय, विद्यालय, विद्या-आलय: 7 परिभाषाएँ"। www.wisdomlib.org। 20 फरवरी 2022 को मूल से संग्रहीत। 20 फरवरी 2022 को लिया गया।
19. ^ जोलाड, शिवकुमार (2 फरवरी 2020)। "मिशनरी और भारत में बड़े पैमाने पर पश्चिमी शिक्षा का विस्तार 1700-1813"। मध्यम। 20 जून 2023 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।
20. ^ बेलेनोइट, हेडन जेए (2007)। "भारत में मिशनरी शिक्षा, धर्म और ज्ञान, लगभग 1880-1915"। आधुनिक एशियाई अध्ययन। 41 (2): 369-394. डीओआई: 10.1017/S0026749X05002143। आईएसएसएन 0026-749X. जेएसटीओआर 4132356। एस2सीआईडी 145084555। 20 जून 2023 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।
21. ^ "भारत में शिक्षा प्रणाली - जीएनयू प्रोजेक्ट - फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन"। जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम. 31 मई 2023 को मूल से संग्रहीत। 14 जून 2023 को लिया गया।



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com